थैलेसीमिया

सन्दर्भ:

- केंद्र सरकार जल्द ही थैलेसीमिया से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन जहां भी आवश्यक हो एक देशव्यापी स्क्रीनिंग अभ्यास, के साथ शुरुआत होगी।

थैलेसीमिया क्या है?

- थैलेसीमिया एक अनुवांशिक पुराना रक्त विकार है, जिसके कारण मरीज के रेड ब्लड सेल्स (आरबीसी) में पाया जाने वाला पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है।
- इससे एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर दो से तीन सप्ताह में रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता होती है।
- थैलेसीमिया वंशागत विकार हैं जो जीन के माध्यम से माता-पिता से बच्चों में आते हैं। प्रत्येक लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन के 240 से 300 मिलियन अणु हो सकते हैं।
- इस रोग की गंभीरता जीन में शामिल उत्परिवर्तन और उनके परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है।

थैलेसीमिया के प्रकार:

- थैलेसीमिया माइनर:
  - थैलीसीमिया माइनर उन बच्चों को होता है, जिन्हें प्रभावित जीन माता-पिता दोनों में से किसी एक से प्राप्त होता है।
  - इस जीन में थैलेसीमिया लक्षण वाले लोगों को वाहक के रूप में जाना जाता है जिन्हें थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है।
  - थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है यह केवल हल्का एनीमिया होता है।
  - **थैलेसीमिया इंटरमीडिया:** ये ऐसे रोगी होते हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर तक लक्षण
- थैलेसीमिया मेजर:
  - यह थैलेसीमिया का सबसे गंभीर रूप है। यह तब होता है जब एक बच्चे को दो उत्परिवर्तित जीन , प्रत्येक माता-पिता से एक अनुवांशिक में मिलते हैं।
  - थैलेसीमिया मेजर वाले रोगी बच्चों में गंभीर रक्ताल्पता के लक्षण उसके प्रथम वर्ष में विकसित हो जाते हैं।
  - जीवित रहने या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (bone marrow transplant) के लिए उन्हें नियमित रूप से ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है और उनमें आयरन के ओवरलोड और अन्य जटिलताओं का गंभीर खतरा होता है।

मुख्य तथ्य:

- भारत दुनिया का सबसे थैलेसीमिया प्रभावित क्षेत्र है, जहां हर महीने 40 मिलियन वाहक (carriers) और 1,00,000 से अधिक थैलेसीमिया मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं।
- देश भर में 1,00,000 से अधिक रोगी इलाज की कमी के कारण 20 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं।
- भारत में थैलेसीमिया का पहला मामला 1938 में दर्ज किया गया था। हर साल भारत में थैलेसीमिया मेजर वाले 10,000 बच्चे पैदा होते हैं।

होते हैं।	

सेना में सामान्य वर्दी

सन्दर्भ:

- भारतीय सेना के ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी अपने रेजिमेंटल या कोर संबद्धता के बावजूद 1 अगस्त 2023 से एक सामान्य वर्दी पहनेंगे।

मुख्य विशेषताएं:

- इस परिवर्तन का उद्देश्य वरिष्ठ नेतृत्व के बीच सामान्य पहचान की भावना को बढ़ावा देना है।
- नई वर्दी में ब्रिगेडियर और जनरलों सहित फ्लैग-रैंक अधिकारियों के लिए मानकीकृत हेडगेयर, कंधे रैंक बैज, गोरगेट पैच, बेल्ट और जूते शामिल होंगे।
- अब डोरी (जो गर्दन, कंधे, या कलाई के चारों ओर पहनी जाने वाली डोरियाँ या पट्टियाँ हैं) वर्दी का हिस्सा नहीं रहेंगी।
- हेडगियर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक हरे रंग की बेरेट कैप होगी और बेल्ट बकल पर यूनिट प्रतीक चिन्ह के बजाय भारतीय सेना का क्रेस्ट होगा।
- अधिकारी आगे की ओर एक ही स्वीकृत पैटर्न वाले काले रंग के ब्रोग जूते भी पहनेंगे।
- जबकि अलग-अलग वर्दी और साज-सज्जा ने ऐतिहासिक रूप से सेना के भीतर विशिष्ट हथियारों, रेजिमेंटों और सेवाओं का प्रतिनिधित्व किया है, अब उद्देश्य कनिष्ठ नेतृत्व और रैंक और फ़ाइल के बीच भाईचारा, एस्प्रिट डे कॉर्प्स और रेजिमेंटल लोकाचार को बढ़ावा देना है।
- यूनिट और बटालियन स्तर पर, पहचान की एक अलग भावना एक ही रेजिमेंट के अधिकारियों और सैनिकों के बीच एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देती है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की वर्दी में कई बदलाव हुए हैं।
- स्वतंत्रता के बाद पहला महत्वपूर्ण बदलाव तब हुआ जब ब्रिटिश शासन के दौरान पहनी जाने वाली खाकी वर्दी से अंतर करने के लिए जैतून के हरे रंग को अपनाया गया।
- पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के बाद, वैश्विक सैन्य रुझानों के साथ संरेखित करने के लिए छलावरण पैटर्न (camouflage patterns) को युद्ध पोशाक के रूप में पेश किया गया था।
- सबसे हालिया परिवर्तन अनधिकृत प्रसार से संबंधित सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए 2022 में "डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट यूनिफॉर्म" की शुरुआत थी।
- सेना ने नई वर्दी के डिजाइन और छलावरण पैटर्न (camouflage patterns) के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) भी प्राप्त किया।

राजस्थान में लिथियम का भंडार

सन्दर्भ:

- हाल ही में राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में पाए गए भंडार से अधिक राजस्थान के डेगाना
  में लिथियम भंडार की खोज की गई है।

मुख्य विशेषताएं:

- इनका दावा है कि ये भंडार भारत की लिथियम की लगभग 80% मांग को पूरा कर सकते हैं।
- सरकार इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए दुर्लभ तत्व की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- लिथियम भंडार दक्षिण अमेरिका - अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में लिथियम त्रिकोण में केंद्रित हैं, इन क्षेत्रों में कुल का 50% केंद्रित है।
- इसमें चीन अन्य देशों से आगे है जो 75% लिथियम रिफाइनिंग को नियंत्रित करता है।
- भारत की 2030 तक ईवी प्रवेश को 30% तक बढ़ाने की योजना लिथियम पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अभी तक, देश में सभी वाहनों की बिक्री का केवल 1% से थोड़ा अधिक इलेक्ट्रिक वाहन हैं।

लिथियम बैटरियों का महत्व:

- लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकमात्र विकल्प है क्योंकि इसमें उच्च शक्ति-से-भार अनुपात होता है, जो इसे वाहन के कर्ब वजन को कम रखते हुए एक बड़ा चार्ज प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- यह अधिक ऊर्जा कुशल है और तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में बेहतर प्रदर्शन करता है। यह इसे अन्य सामग्रियों की तुलना में अधिक सुरक्षित, अधिक विश्व

केंद्रीय बैंक द्वारा गोल्ड रश

सन्दर्भ:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अक्तूबर 2022 से मार्च 2023 तक वित्त वर्ष 2022-23 में RBI का स्वर्ण भंडार 794.64 मीट्रिक टन तक पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2021-22 (760.42 मीट्रिक टन) से लगभग 5% अधिक है।
- 31 मार्च, 2023 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $578.449 बिलियन था जिसमे सोने का भंडार $45.2 बिलियन था।

मुख्य विशेषताएं:

- सिंगापुर, चीन और तुर्की के केंद्रीय बैंक भी सोना खरीद रहे हैं।
- वर्ष 2022 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने रिकॉर्ड 1,136 टन सोना खरीदा।
- तुर्की के केंद्रीय बैंक ने 2022 में सबसे बड़ी खरीद

विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में:

- विदेशी मुद्रा भंडार या फोरेक्स रिजर्व एक केंद्रीय बैंक या अन्य मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा, स्वर्ण भंडार, ट्रेजरी बिल आदि जैसी परिसंपत्तियां हैं।
- अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में हैं।

(148 टन से 542 टन तक) दर्ज की।

इन भण्डारों को बढ़ाने के पीछे के कारण :

- विविधीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आरबीआई अपने भंडार में सोना का भंडार कर रहा है।
    - वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ती मुद्रास्फीति परिदृश्य के बीच अपने रिटर्न को सुरक्षित रखने के लिए सोने को अधिक सकुशल सुरक्षित और तरल संपत्ति माना जाता है।
- रणनीति में यह बदलाव अतीत में नकारात्मक ब्याज दरों, डॉलर के कमजोर होने और भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने से प्रेरित है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खरीदा गया सोना:
    - आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में 34.22 टन सोना खरीदा।
    - वित्त वर्ष 2022 में इसने 65.11 टन सोना जमा किया था।
    - 30 जून, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष और वित्तीय वर्ष 2023 के बीच आरबीआई के सोने के भंडार में 228.41 टन की वृद्धि हुई।
    - 437.22 टन सोना विदेशों में बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के पास सुरक्षित अभिरक्षा (safe custody) में रखा गया है और 301.10 टन सोना घरेलू स्तर पर रखा गया है।
    - कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी मार्च 2022 के अंत में लगभग 7% से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में

- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:
    - विदेशी मुद्रा संपत्तियां।
    - स्वर्ण भंडार।
    - विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)।
    - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ आरक्षित स्थिति।

महत्व :

- विदेशी मुद्रा भुगतान संतुलन संकट की संभावना को कम करता है।
- यह विनिमय दरों और अव्यवस्थित बाजार स्थितियों पर दबाव के खिलाफ आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है, और नीतिगत स्वायत्तता के लिए जगह बनाता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि उनकी राष्ट्रीय मुद्रा तेजी से अवमूल्यन करती है या पूरी तरह से दिवालिया हो जाती है तो आरबीआई के पास बैकअप फंड है।
- यदि विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि के कारण रुपये का मूल्य घटता है तो आरबीआई भारतीय मुद्रा बाजार में डॉलर बेचता है ताकि भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास की जांच की जा सके।
  एक अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी व्यापार को आकर्षित करने में मदद करता है और व्यापारिक भागीदारों में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करता है।

लगभग 7.81% हो गई।	

मेडिकल टूरिज्म (Medical Tourism)

सन्दर्भ:

- भारत का लक्ष्य इस वर्ष अपनी जी20 अध्यक्षता के तहत मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) के माध्यम से दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को खत्म करना है।

मुख्य विशेषताएं:

- चिकित्सा पर्यटन सूचकांक 2020-2021 (MTI) के अनुसार, भारत चिकित्सा पर्यटन के लिए विश्व स्तर पर दसवें स्थान पर है।
- भारत ने एमवीटी से 2015, 2016 और 2017 में क्रमशः ₹1,35,193 करोड़, ₹1,54,146 करोड़ और ₹1,77,874 करोड़ विदेशी मुद्रा कमाए।
- नीति आयोग का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 तक एमवीटी और वेलनेस टूरिज्म से अतिरिक्त $9 बिलियन कमा सकती है।

सरकारी पहल:

- भारत ने चिकित्सा पर्यटन के केंद्र के रूप में भारत को बढ़ावा देने के लिए 27 और 28 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में 'वन अर्थ वन हेल्थ - एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया - 2023' कार्यक्रम की मेजबानी की।
- इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत से चिकित्सा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) विशेषज्ञों, उद्योग हितधारकों और पेशेवरों के लिए नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना है।
- सरकार ने भारत को स्वास्थ्य और चिकित्सा पर्यटन स्थल के रूप में बाजार में लाने के लिए

मेडिकल टूरिज्म के बारे में:

- मेडिकल टूरिज्म को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, हेल्थ टूरिज्म या ग्लोबल हेल्थकेयर के नाम से भी जाना जाता है।
- यह चिकित्सा सेवाओं, मुख्य रूप से वैकल्पिक या जटिल सर्जरी की तलाश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर यात्रा करने का अभ्यास है।
- चिकित्सा पर्यटन के हितधारकों में अन्य के साथ-साथ एयरलाइन, अस्पताल, आरोग्य केंद्र और होटल शामिल हैं।
- वर्तमान में इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए सबसे अधिक मांग वाला स्थान कनाडा अपने अनुकूल वातावरण, मजबूत मेडिकल टूरिज्म उद्योग और उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं और सेवाओं के साथ है।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल अपने नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कनाडा के अधिकांश सरकारी अस्पताल भी विदेशी रोगियों की सेवा करते हैं।

भारत के मेडिकल टूरिज्म पसंदीदा होने का कारण:

- लागत प्रभावी स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता।
- गुणवत्ता निदान उपकरण (quality diagnostic equipment) और प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपस्थिति, जिनमें से कई अंग्रेजी धाराप्रवाह में हैं।

'हील इन इंडिया' अभियान शुरू किया है।
- भारत ने 156 देशों के एमवीटी यात्रियों के लिए ई-वीजा लॉन्च किया है और भारतीय चिकित्सा उद्योग में उनकी स्थिति को औपचारिक रूप देते हुए आयुष केंद्रों को भी मान्यता दी है।

- भारत में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियां भी हैं, जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)

सन्दर्भ:

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सेवानिवृत्त अधिकारी का कार्यकाल केवल असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाने के अपने 2021 के फैसले पर फिर से विचार करेगा
- अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति में 2021 से सुनवाई कर रही थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बारे में:

- ईडी एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और उसके अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है।
- 1 मई 1956 को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था।
- वर्ष 1957 में, इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया।

कार्य :

- यह निम्नलिखित दो कानूनों को लागू करता है।
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा)।
  - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए)।
- मूल मंत्रालय:
  - यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का हिस्सा है।
- संघटन :
- इसकी अध्यक्षता प्रवर्तन निदेशक करते हैं, जो एक आईआरएस अधिकारी (भारतीय राजस्व सेवा) होते है।
- मुख्यालय : नयी दिल्ली।
- पूरे देश में इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

संक्षिप्तसुर्खियां

पर्सोना नॉन ग्रेटा

सन्दर्भ:

- कनाडा द्वारा उसके राजनेता को डराने-धमकाने के अभियान में शामिल होने के आरोपों पर एक चीनी राजनयिक को निष्कासित करने की घोषणा के एक दिन बाद, चीन ने शंघाई में एक कनाडाई राजनयिक को अवांछित व्यक्ति(Persona non grata) घोषित किया।

पर्सोना नॉन ग्रेटा:

- पर्सोना नॉन ग्रेटा एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है "अवांछित व्यक्ति।"
- कूटनीति में यह एक राजनयिक या विदेशी व्यक्ति से संदर्भित होता है जिसका किसी देश में प्रवेश करना या रहना उस देश द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- सन 1961 के वियना कन्वेंशन फॉर डिप्लोमैटिक रिलेशंस में इस पदनाम को राजनयिक अर्थ मिला।
- इस संधि के अनुच्छेद-9 में उल्लेख किया गया है कि कोई देश किसी भी समय अपने निर्णय की व्याख्या किए बिना राजनयिक स्टाफ के किसी भी सदस्य को अवांछित व्यक्ति घोषित कर सकता है।
- ऐसी घोषणा के तुरंत बाद, संबंधित व्यक्ति आमतौर पर अपने गृह देश लौट जाता है।
- यदि वे उचित अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो वह देश संबंधित व्यक्ति को मिशन के सदस्य के रूप में मान्यता देने से इंकार कर सकता है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी देश में आने से पहले ही अवांछित व्यक्ति घोषित किया जा सकता है।

हाइफ़ा

सन्दर्भ:

- हाल ही में इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि अरब ट्रेन नेटवर्क भविष्य में भारतीय सामान को हाइफा के इजरायली बंदरगाह तक ले जाएगी।

हाइफा के बारे में:

- हाइफ़ा इज़राइल के उत्तरी तट पर स्थित एक शहर है। यरुशलम और तेल अवीव के बाद यह देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। हाइफ़ा इज़राइल का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है।
- हाइफा माउंट कार्मेल की ढलानों पर स्थित है, जहां से भूमध्य सागर दिखता है।
- बंदरगाह तेल, रसायन और विभिन्न कार्गो शिपमेंट सहित सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला को संभालता है।

- **आकर्षण:** हाइफा आगंतुकों के लिए कई आकर्षण और स्थलचिह्न प्रदान करता है। सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक बहाई गार्डन है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो अपने सीढ़ीदार उद्यानों और आश्चर्यजनक दृश्यों के लिए जाना जाता है।

तुंगनाथ मंदिर

सन्दर्भ:

- हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

मुख्य विशेषताएं:

- यह मंदिर हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है जो उत्तराखंड के पांच पंचकेदारों में से तीसरे के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर को समुद्र तल से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एशिया का सबसे ऊंचा प्राचीन 'शिवलालय' होने का गौरव प्राप्त है। यह भगवान शिव को समर्पित सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक और पांच पंच केदार मंदिरों में सबसे ऊंचा है।

अमेरिकी ऋण सीमा (U.S. Debt Ceiling)

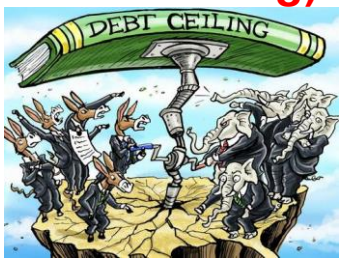

सन्दर्भ:

- हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी सचिव ने कांग्रेस को सूचित किया कि यदि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और राष्ट्रपति जो बिडेन के व्हाइट हाउस में कर्ज की सीमा को बढ़ाने या निलंबित करने के लिए आम सहमति नहीं बनती है तो देश 1 जून, 2023 की शुरुआत में अपने ऋण पर चूक कर सकता है।

ऋण सीमा के बारे में:

- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में ऋण सीमा की शुरुआत की गई थी।
- यह अधिकतम राशि है जो अमेरिकी संघीय सरकार अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए उधार ले सकती है।
- चूंकि सरकार करों और अन्य राजस्वों के माध्यम से कमाई से अधिक खर्च करती है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा लाभ, सैन्य आदि जैसे खर्चों का भुगतान करने के लिए उसे धन उधार लेने की आवश्यकता होती है।
- इस उधार सीमा को 2021 में बढ़ाकर $31.4 ट्रिलियन कर दिया गया।

ऋण की उच्चतम सीमा को पार करने के परिणाम :

- ट्रेजरी सचिव ने चेतावनी दी कि यदि वे जून तक ऋण सीमा बढ़ाने में विफल रहे, तो सरकार अपने ऋण पर चूक जाएगी, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है।

	• विश्लेषकों का कहना है कि एक बार ऋण चूक हो जाने पर डॉलर कमजोर होगा, शेयर बाजार गिरेंगे।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare